घटेगा यूपी की चीनी मिलों का मुनाफा

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 22 फरवरी

उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और लागत से कम भाव पर चीनी की बिक्री की वजह से 2012-13 (अक्टूबर-सितंबर) चीनी सत्र में परिचालन मुनाफे में कमी आएगी। केयर रेटिंग के एक अध्ययन रिपोर्ट में यह सामने आया है। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह गन्ने की बढ़ी हुई खरीद कीमत है, जो उद्योग के परिचालन लागत का करीब 80-85 प्रतिशत होता है।

केंद्र सरकार हर साल गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है तो गन्ना किसानों को भुगतान करना होता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब में राज्य सरकारें न्यूनतम मूल्य तय करती हैं, जिस भाव से मिलों को गन्ना खरीदना होता है। इसे राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां राज्य सरकारें गन्ने के दाम नहीं तय करती हैं, वहां भी चीनी मिलों को गन्ने के दाम का भुगतान एफआरपी से अधिक करना पड़ता है। मिलें इसलिए किसानों को ज्यादा भुगतान करती हैं कि वे ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों। इस तरह से प्रति टन चीनी की लागत कंपनी के संयंत्र स्थल के मुताबिक अलग अलग होती है।

यूपी की चीनी मिलों को गन्ने के लिए सबसे ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी लागत बढ़ी है

पिछले कुछ साल से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से घोषित राज्य समर्थन मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के गन्ने के दाम में अंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले दो साल में यह अंतर 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। चीनी सत्र 2012-13 में यह अंतर बढ़कर 55 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इसके चलते उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को तुलनात्मक रूप से गन्ने के ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं और उनका उत्पादन लागत ज्यादा है।

यूपी में एसएपी ज्यादा होने की वजह से राज्य में चीनी की उत्पादन लागत पश्चिम और दक्षिण भारत में स्थित चीनी मिलों की तुलना में अधिक है। 2009-10 से 2011-12 चीनी सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश इलाके में चीनी के उत्पादन लागत में 7.8 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान दक्षिण भारत की मिलों के उत्पादन लागत में 4.1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। बहरहाल महाराष्ट्र में इस अवधि में गन्ने के दाम कुछ कम होने की वजह से यहां की चीनी मिलों के उत्पादन लागत में 1 रुपये प्रति किलो की कमी आई है।

जानकारों का मानना है कि चीनी उत्पादन के लागत में बढ़ोतरी से देश भर की चीनी मिलों के मुनाफे पर असर पड़ा है, लेकिन इसका असर उत्तर भारत के राज्यों में स्थित मिलों पर ज्यादा है।

यूपी की मिलों को 2 रुपये किलो का घाटा

चीनी सत्र 2012-13 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसएपी में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी, जो 280 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तमिलनाडु और कर्नाटक में इस दौरान गन्ने की कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इस दौरान कीमतों में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और राज्य में गन्ने के दाम 250 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। केयर रेटिंग का अनुमान है कि 2012-13 में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की उत्पादन लागत 4.4 रुपये प्रति किलो बढ़कर 34 रुपये प्रति किलो हो जाएगी, जो चीनी खरीद मूल्य से ज्यादा है। वहीं दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की चीनी मिलों की उत्पादन लागत क्रमश: 28 रुपये और 27 रुपये प्रति किलो रहने की उम्मीद है। केयर के मुताबिक 2012-13 के दौरान चीनी के औसत दाम 33-34 रुपये प्रति किलो रहने की उम्मीद है।